राजमार्गों पर ई-वाहन चार्ज करने की सुविधा बढ़ेगी

तैयारी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सरकार का विजन 2047 के तहत देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के जाल बिछाने के साथ हरित उर्जा को बढ़ावा देने पर जोर है। इसके तहत प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेस-वे पर इलेक्ट्रानिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों का बुनियादी ढांचा खड़ा किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 12,000 नए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोले का लक्ष्य रखा गया है।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू कर दी है। इसमें ई-वाहनों की बैटरी को सस्ता करने और चार्जिंग स्टेशनों पर कम समय में चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अधिकारी ने बताय कि ई-वाहन लंबी दूरी के लिए अव्यवहारिक हैं। क्योंकि शहरों के बार राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार्जिंग स्टेशनों का अभाव है। विजन 2047 में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ चार्जिंग स्टेशन को बुनियादी ढांचा खड़ा किया जाएगा। इससे लंबी दूरी का सफर ई-वाहनों से संभव होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के प्रति आम जनता में रुझान बढ़ा है। इसकी बिक्री में और उछाल आएगा।

इसरो को सस्ती बैटरी बनाने का काम सौपा

सरकार ने इसरो को सस्ती व टिकाऊ बैटरी बनाने का काम सौपा है। नीति में ई-वाहन के पंजीकरण, वैट टैक्स में छूट सहित सब्सिडी का प्रावधान है। जिससे ई-वाहनों की कीमत पेट्रोल-डीजल वाहन के बराबर लाई जा सके। इससे दो पहिया, चार पहिया निजी व व्यावसायिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार ई-वाहन व हरित उर्जा वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई मोर्चो पर काम कर रही है। इसके तहत 2030 तक पेट्रोल-डीजल पर 85 फीसदी खपत की निर्भरता को 60 प्रतिशत पर लाना चाहती है। इससे एक अनुमान के मुताबिक अगले दस साल में 60 अरब डालर के डीजल-पेट्रोल पर बचत होगी।

एक गीगाटन (एक अरब टन) तक कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रायल ग्रीन एनर्जी जैसे सीएनजी, बॉयो-सीएनजी, एचसीएनजी को लेकर पहले की मानक बना चुका है। ग्रीन एनर्जी की दिशा में अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, दक्षिण कोरिया आदि देश आगे बढ़ रहे हैं।